



भारत की स्वदेशी जनजातियों के लिये कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के नहितारथ

प्रलिस के लिये:

[कॉन्फरेंस ऑफ पार्टिज़ \(COP15\)](#), कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, सतत विकास लक्ष्य

मेन्स के लिये:

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क, COP15 के परणाम, पर्यावरण प्रदूषण और कषरण, स्वदेशी समुदाय

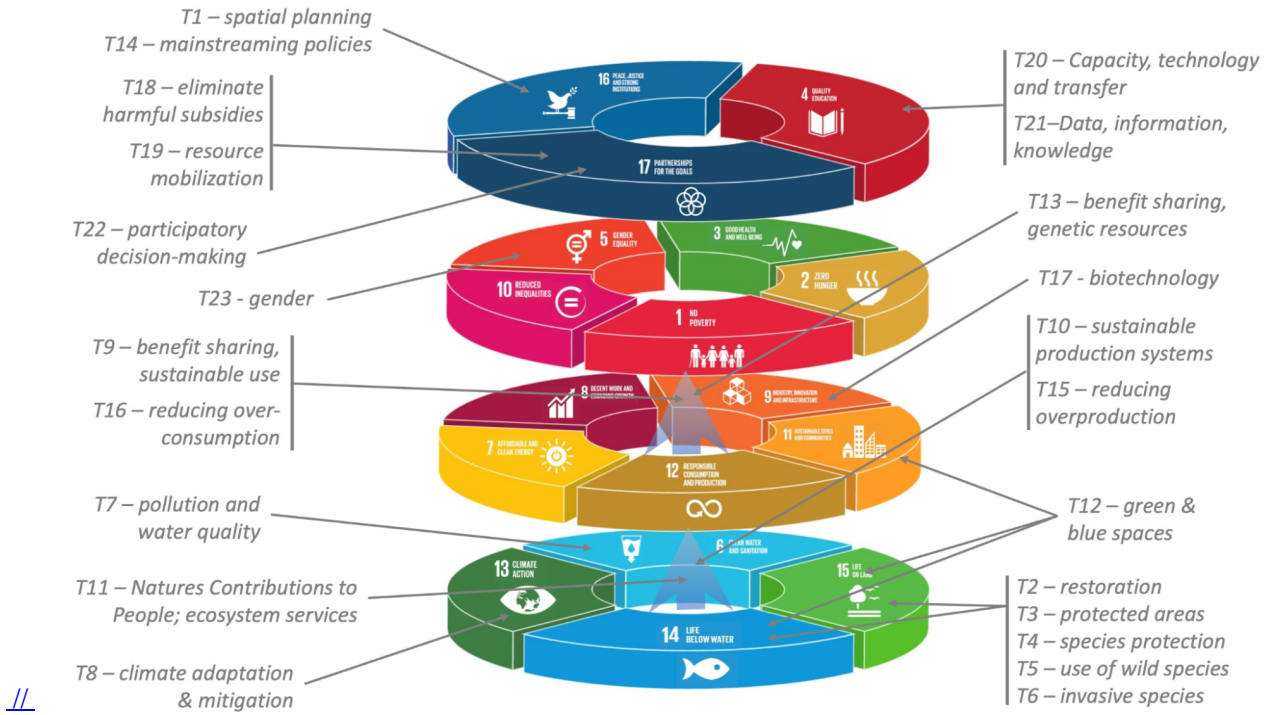
[स्रोत: द हट्टि](#)

चरचा में क्यों?

हाल ही में एरज़ोना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में [कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क \(Global Biodiversity Framework- GBF\)](#) और इसके संभावित प्रभाव, विशेष रूप से भारत की स्वदेशी जनजातियों पर, से संबंधित चर्चाओं पर प्रकाश डाला गया।

कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क क्या है?

- **परिचय:** जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन (COP15) में "कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क" (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework- GBF) को दिसंबर 2022 में अपनाया गया है।
 - इसका उद्देश्य [सतत विकास लक्ष्य](#) की प्राप्ति का समर्थन करना और पछिली रणनीतिक योजनाओं पर निर्माण करना है।
 - फ्रेमवर्क में **वर्ष 2050 के लिये चार लक्ष्य और वर्ष 2030 के लिये 23 लक्ष्य** निर्धारित किये गए हैं, जसमें योजना, नगरानी, रिपोर्टिंग, वित्त तथा क्षमता विकास शामिल हैं।
 - GBF के लक्ष्य 3 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक संरक्षित क्षेत्रों को मौजूदा 16% की तुलना में विश्व के स्थलीय क्षेत्र के कम-से-कम 30% तक बढ़ाना है।
 - सभी दल (भारत सहित) GBF को लागू करने के लिये राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।



■ भारत की प्रगतः

- **लक्ष्य 3- 30x30:** भारत अपने 22% स्थलीय क्षेत्र और 5% समुद्री तथा तटीय क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत लाने की रिपोर्ट करता है।
 - हालाँकि भारत में संरक्षित क्षेत्रों के वसुतार में प्रगतः हुई है, कतः गैर-संरक्षण उद्देश्यों के लः इन क्षेत्रों का आवंटन चतःजनक है।
 - **भारत के वन (संरक्षण) संशोधन अधनःयः 2023** द्वारा सतत् वकःस के प्रतः प्रतःबिद्धता को दर्शाते हुए चड़ःधःघर और पारस्थःतःकः परःटन जैसे वाणःजःयःकः उद्ःयःओं को शामिल करने के लः वन संबंधी गतःवःधःयःओं को पुनः परःभःषतः कःया गःया।
 - हालाँकि सर्वोच्च नःयाःलय द्वारा जःरी नःरःदेश के अनुसार वन क्षेत्रों (संरक्षःतः क्षेत्रों को छोड़कर) के भीतर चड़ःधःघर और सफःरी स्थापतः करने के कःसी भी प्रःस्ताव के लः नःयाःलय से पूर्व अनुमोदन प्रापःत करना अनःवारःय है।
 - अन्य प्रःभावी क्षेत्र-आधारःतः संरक्षण उपाय (OECMs): भारत ने नागरःकः-नेतृत्व वाली पहल सहःतः OECMs की 14 श्रेणःयःओं की पहचान की है, कतः उनकः घोषणा की स्वैच्छःकः प्रकृतः वःधःकः सुरक्षा संबंधी चतः उत्पन्न करती है।

भारत की मूल जनजातःयःओं पर वन वसुतार का कःया प्रभाव हो सकता है?

- **नःहितःरःथः** GBF लक्ष्यों के तहत वन वसुतार पारंपरःकः भूमः उपयोग प्रथाओं और प्राकृतःकः संसाधनों पर नःरःभर स्वदेशी समुदायों की आःवःकः पर प्रतःकूल प्रभाव डाल सकता है, जसःसे स्वदेशी आबादी के बीच गरीबी तथा खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।
 - भारत के लगभग 84% राष्टःरीय उद्ःयान स्वदेशी लोगों द्वारा बसाए गए क्षेत्रों में स्थापतः कःयः गए थे और GBF लक्ष्यों को पूरा करने पर वःशःष बल दःया जाना उनके अस्तःतःव के लः खतरा उत्पन्न कर सकता है।
- **संबंधःतः हालःया उदाहरणः** राजस्थान के कुम्भलगढ़ वन्यःजःव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य में बदलने की पहल से 162 जनजातीय गाँव वसुतःपतः हो सकते हैं।
 - मध्य प्रदेश में नौरादेही अभयारण्य की वसुतार योजना 62 जनजातीय बहुल गाँवों को प्रभावतः कर सकती है।
 - असम में बराक भुवन वन्यःजःव अभयारण्य की अधःसूचना खासी, दमिासा और अन्य स्वदेशी समूहों के लः जोखमः पैदा करती है।

नोटः यह नकारात्मक प्रवृत्तः अन्य दक्षःणः पूर्व एशःयःई देशों में भी वदःयमान है जहाँ मूल नःवासःयःओं को संरक्षःतः क्षेत्रों में बुनःयादी अधिकारों के अभाव का सामना करना पड़ता है। इसके उदाहरणों में **इंडोनेशःया के उजुंगकुलोन नेशनल पार्क** शामिल है जहाँ इस क्षेत्र से संबंधःतः मूल नःवासःयःओं को **आवास, स्वास्थःय, शकःषा, वदःयुत और सुरक्षा** जैसे अधिकारों से वंचतः कःया गःया।

भारत जैववःधःतः संरक्षण में स्वदेशी जनजातःयःओं का उपयोग कैसे कर सकता है?

- **इकोटूरज़िम के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व में इकोटूरज़िम पहल का समर्थन करना, सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना और आय सृजति करना।
 - इसका एक असाधारण उदाहरण केरल के **वायनाड जनजात विरासत ग्राम** हैं, जहाँ समुदाय के नेतृत्व वाली इको-पर्यटन परियोजनाओं ने न केवल आय सृजन में वृद्धि की है अपितु वन्यजीवों की सुरक्षा भी की है और साथ ही स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाया है।
- **पारंपरिक और व्यावसायिक ज्ञान को एकीकृत करना:** सरकार स्वदेशी जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठा सकती है, जैसे मेघालय की **खासी और जैन्तिया जनजातियों** में "**पवतिर उपवनों** (स्थानीय वर्जनाओं और प्रतबिंधों के माध्यम से संरक्षित प्राकृतिक वनस्पति के क्षेत्र)" की रक्षा करने की एक समृद्ध परंपरा है।
 - इस ज्ञान को **भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII)** जैसे संस्थानों के वैज्ञानिक सर्वेक्षणों के साथ एकीकृत करके व्यापक संरक्षण योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
- **सह-प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देना:** पश्चिम बंगाल संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) कार्यक्रम जैसे सह-प्रबंधन मॉडल का वसितार करना जहाँ स्वदेशी समुदाय संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन के लिये वन विभागों के साथ कार्य करते हैं। यह उनके ज्ञान का उपयोग कर उनमें स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- **निःशुल्क, पूर्व और सूचित सहमति:** भारत सरकार निःशुल्क, पूर्व और सूचित सहमति (FPIC) को बरकरार रखती है, जो **पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक वसितार) अधिनियम, 1996** के तहत जनजातीय भूमि पर संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना से पूर्व एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- **सामाजिक प्रभाव आकलन:** मौजूदा आजीविका पर संरक्षित क्षेत्र वसितार के संभावित प्रभाव को समझने के लिये **सामाजिक प्रभाव आकलन** करने की आवश्यकता है।
 - **नामीबिया के सांप्रदायिक संरक्षण कार्यक्रम** के उदाहरण के बाद, संरक्षित क्षेत्रों के लिये सह-प्रबंधन मॉडल स्थापित किये जा सकते हैं।
 - ये मॉडल स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्वदेशी समुदायों को वन्यजीव प्रबंधन में हसिसेदारी प्रदान करते हैं।
- **नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना:** भारत को यह सुनिश्चित करते हुए **किईमानदार संरक्षण प्रयासों के साथ-साथ स्वदेशी अधिकारों और ज्ञान प्रणालियों का सम्मान** किया जाता है, अपनी राष्ट्रीय नीतियों को स्वदेशी लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples- UNDRIP) सिद्धांतों के साथ संरेखित करना चाहिये।

प्रश्न. भारत की स्वदेशी जनजातियों पर कुनमिंग-मॉन्ट्रियल GBF के प्रभाव से उत्पन्न संभावित खतरों का आकलन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

Q. "मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाड" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है ? (2018)

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल
- UNEP सचिवालय
- UNFCCC सचिवालय
- वशिव मौसमवर्ज्ञान संगठन

उत्तर: (c)